RNI NO. MPHIN/2022/85285
डाक पंजी. क्र.- MP/KDW/93/2023-24
Email id: haldharkisankgn@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

वर्ष 02 अंक 12 | फरवरी 2024 | पृष्ठ- 8 मूल्य- 5.00 रुपए

अंतरित बजट: 2000 करोड़ रुपए बढ़ा देश का कृषि बजट

तिलहनों के लिए चलेगा आत्मनिर्भर अभियान, डेयरी को मिलेगा बढ़ावा

हलधर किसान

नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी दूसरे कार्यकाल का अंतिम अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठी बार बजट पेश किया। इस बजट के केंद्र में गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता रहे। कृषि के लिए भी इस बजट में कई एलान हुए। बजट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.27 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इस बार बजट में वित्तमंत्री ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उपायों का जिक्र करते हुए कहा कि कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा। डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा, दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। 1361 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा, तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा

एमएसपी का दायरा और सम्मान निधि की रकम नहीं बढी

मिलेगा।

सरकार ने वित्त वर्ष 2024.25 के लिए कृषि क्षेत्र को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले केवल 2 प्रतिशत यानी 2,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। सरकार ने पिछले साल 2023-24 कृषि बजट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए थे, जबकि 22.23 में यह बजट 1.24 लाख रुपए था। बजट में जिस तरह उम्मीद की जा रही थी कि, सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा नहीं बढ़ाया है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की राशि को भी नहीं बढ़ाया है, यह 6,000 रुपए ही रहेगी।

बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डबल यानी सालाना 6000 से बढ़कर 12000 रुपए की जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इस बार कृषि क्षेत्र को क्या मिला?

लोकसभा चुनावों से पहले पेश हुए अंतरिम बजट में सरकार ने ग्रामीण विकास पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। पीएम.किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर वर्ष सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया है। अनेक दूसरे कार्यक्रमों के अलावा इन उपायों से अन्नदाता को देश और पूरी दुनिया के लिए अन्न पैदा करने में सहायता दी जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1361 मंडियों को एकीकृत कर दिया है और इसमें 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कारोबार हो रहा है और 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही हैं।

कृषि.क्षेत्र समावेशी, संतुलित, उच्चतर संवृद्धि और उत्पादकता की ओर अग्रसर है। इन्हें कृषक.केंद्रित नीतियां लाकर, किसानों को उनके आय अर्जन में सहायता देकर, कीमत और बीमा के माध्यम से जोखिम कवरेज देकर, स्टार्ट.अप के माध्यम से प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देकर सुगम किया गया है।

पिछले बजट में यह किए थे ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023.24 का बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए कई एलान किए थे। सरकार ने वित्त वर्ष 2023.24 के लिए किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने की घोषणा की थी। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी थी। इस दौरान उन्होंने बजट में सात प्राथमिकताएं गिनाई थीं। पहली प्राथमिकता के रूप में किसान, महिला, ओबीसी, एससी.एसटी, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को तक समग्र विकास पहुंचाने की बात कही गई थी।

इसी प्राथमिकता के तहत कृषि के लिए डिजिटल लोक अधोसंरचना का निर्माण की घोषणा हुई थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि इससे किसानों को खेती की योजना बनाने, बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उत्पादन क्षमता और लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ेगी। किसान, सरकार और उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ेगा। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाने की घोषणा भी हुई थी ताकि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। वित्त मंत्री ने मोटे अनाज को लेकर भी एलान किए थे।

कृषि क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं-

. सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी।
. सभी कृषि.जलवायु क्षेत्रों में नैनो.डीएपी के इस्तेमाल का विस्तार किया जाएगा।
. तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान शुरू किया जाएगा।
. डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा।
. जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात दोगुना करने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।
. पांच एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे।

ये थीं कृषि क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं-

. 20 लाख क्रेडिट कार्ड- केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ाने की घोषणा की थी। वित्त वर्ष 2023.24 के लिए 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया था।

. किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर- किसानों के लिए किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात कही गई थी। यहां किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी।

. एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा- केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया था। कृषि स्टार्टअप के लिए कृषि निधि के नाम से डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनाने का एलान किया गया था। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफसे मदद देने की बात कही गई थी।

. मोटे अनाज को बढ़ावा- सरकार ने पिछले बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से श्री अन्न योजना की शुरुआत की थी। इसके जरिए देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था।

. बागवानी के लिए- सरकार ने पिछले बजट में बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की राशि आवंटित की थी। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया था।

मछली पालन को बढ़ावा- केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया था। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देना बताया गया था।

. प्राकृतिक खेती के लिए मदद- पिछली बार वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

. सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापनारू सरकार ने एलान किया था कि वह अगले पांच वर्षों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी।

डिसक्लेमर: उपर व्यक्त विचार कार्टूनिस्ट के स्वयं के है।

तीन नदियों को जोड़ेगी सरकार, 26 जिलों के किसानों को मिलेगी सिंचाई की सुविधा

देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मप्र सरकार कई नई परियोजनाएं शुरू करने जा रही है। इसमें पार्बती, कालीसिंध एवं चंबल नदी को जोड़ने की महती योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरु कर दी गई है।

इसके लिए 28 जनवरी को मध्यप्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में सचिव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय श्रीमती देबाश्री मुखर्जी, मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन डॉ. राजेश राजौरा और राजस्थान शासन के अपर मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगभग दो दशकों से लंबित पार्बती.कालीसिंध.चंबल परियोजना अब मूर्त रूप ले सकेगी। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के चंबल और मालवा अंचल के 13 जिलों को लाभ पहुंचेगा। प्रदेश के ड्राई बेल्ट वाले जिलों जैसे मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और औद्योगिक बेल्ट वाले जिलों जैसे इंदौर, उज्जैन, धार, आगर.मालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ के औद्योगीकरण को और बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के मालवा और चंबल अंचल में लगभग तीन लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा बढ़ेगा। परिणामस्वरूप इन अंचलों के धार्मिक और पर्यटन केंद्र भी विकसित होंगे। यह परियोजना निश्चित रूप से पश्चिमी मध्यप्रदेश के लिए एक वरदान है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यह परियोजना 5 वर्ष से कम समय में फलीभूत होगी, जिसकी वर्तमान लागत लगभग 75000 करोड़ रुपए है। प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ आबादी इस परियोजना से लाभान्वित होगी। यह परियोजना प्रदेश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जैसी समस्याओं का समाधान कर प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी।

इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज का दिन मध्यप्रदेश और राजस्थान के पानी की कमी वाले 26 जिलों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। परियोजना से लगभग 5.60 लाख हैकटेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही बांधों और बड़े तालाबों में पानी का संचय कर जल.स्तर उठाने में सफलता प्राप्त होगी। पार्बती.कालीसिंध.चंबल परियोजना को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से एकीकृत कर इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा देते हुए अत्यंत कम समय में मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच सहमति बनी जिसके लिए दोनों सरकारें बधाई की पात्र हैं। यह परियोजना सहकारी संघवाद का स्वर्णिम उदाहरण है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि इस परियोजना से राजस्थान और मध्यप्रदेश के चंबल बेसिन के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद होगी जिससे दोनों राज्यों के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को फायदा मिलेगा, और भविष्य में दोनों राज्यों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे।

दोनों राज्यों के 26 जिलों को मिलेगा लाभ

त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन में इस लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यों में कुल 5.60 लाख हैक्टेयर क्षेत्र म सिंचाई प्रदान करने के साथ.साथ पूर्वी राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिये पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

समझौता ज्ञापन में लिंक परियोजना के काम का दायरा, पानी का बंटवारा, पानी का आदान.प्रदान, लागत और लाभ का बंटवारा, कार्यान्वयन तंत्र और चंबल बेसिन में पानी के प्रबंधन और नियंत्रण की व्यवस्था शामिल की गई हैं। उल्लेखनीय है कि पार्बती. कालीसिंध. चंबल लिंक परियोजना की फीजिबिलिटी रिपोर्ट फरवरी 2004 में तैयार की गई थी तथा वर्ष 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा आरसीपी का प्रस्ताव लाया गया था। वर्तमान समझौता ज्ञापन में दोनों परियोजनाओं को एकीकृत कर दिया गया है।

मप्र के खरगोन जिले में फसलों पर ड्रोन से होने लगा दवाईयों का छिडकांव

हलधर किसान

खरगोन मप्र (तकनिक)। भारत कृषि प्रधान देश है। यहां के दो तिहाई लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से कृषि से जुड़े हैं, जिस कारण समय.समय पर कृषि क्षेत्र में कई शोध किए जाते है, साथ ही कृषि में कई टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जा रहा है। मप्र के किसान भी अब आधुनिक तकनिक के रुप में फसलों के रखरखाव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे है। कृषि में ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी उपयोगी साबित हो रही है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों को फसलों में गिला खाद और दवाई के छिड़काव में मदद मिलती है।

फसलें रोग मुक्त रहें, इसके लिए किसान खेतों में जाकर जहरीली कीटनाशक दवाएं लगाते हैं। इसमें समय तो अधिक लगता ही है, जोखिम भी रहता है। दवा के छिड़काव की इस पुरानी परंपरा को त्याग कर किसान नई तकनीक अपना रहे हैं। ड्रोन से फसलों के उपचार की तकनीक किसानों को खूब भायी है। महेश्वर विकासखण्ड के ग्राम मोगावा के किसान गुलाबचंद पाटीदार ने आज 02 फरवरी को अपने खेत में लगी चने की फसल में ड्रोन का उपयोग कर कीटनाशक का छिड़काव किया है। उन्होंने जिले के अन्य किसानों को भी अपने खेतों में लगी फसलों में ड्रोन का उपयोग कर कीटनाशकों का छिड़काव करने की सलाह दी है। किसान गुलाबचंद पाटीदार ने बताया कि ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करने पर बहुत सुविधा हो जाती है। इससे कम समय में अधिक रकबे में कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। इससे समय और श्रम की बचत होती है। किसान गुलाबचंद पाटीदार अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गए हैं।

बुरहानपुर से केले की उपज पहुंची इराक, ईरान, दुबई, बहरीन, तुर्की

हलधर किसान. भोपाल। मध्यप्रदेश ने तेजी से वैश्विक कृषि निर्यात बाजार में अपना स्थान बना लिया है। प्रदेश के बुरहानपुर जिले से इराक, ईरान, दुबई, बहरीन और तुर्की को सालाना 30 हजार मीट्रिक टन केले का निर्यात हो रहा है। बुरहानपुर केले की प्रसिद्धि दूर.दूर तक पंहुच गई है। केला उत्पादक किसानों की मेहनत और सरकार की मदद ने बुरहानपुर को एक नई पहचान दिलाई है। लगभग 19000 केला उत्पादक किसान 23,650 एकड़ क्षेत्र में केले की फसल ले रहे हैं। इसमें बुरहानपुर से ही सालाना औसत 16.54 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। एक जिला.एक उत्पाद योजना में केले को शामिल करने के बाद केला उत्पादक किसानों ने उत्साहपूर्वक निर्यात अवसरों का भरपूर लाभ उठाया है।

कृषि निर्यात बाजार में किसानों की गहरी रुचि, कृषि व्यापार के मज़बूत बुनियादी ढांचे और निर्यात कंपनियों की अच्छी उपस्थिति के कारण बुरहानपुर केले को अच्छा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल गया है। यहां मुख्य रूप से जी.9, बसराई, हर्षाली, श्रीमंथी किस्में उगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना में केला उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल रहा है। परिणामस्वरुप बुरहानपुर में 30 केला चिप्स प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित हैं। कुछ इकाईयां केले का पाउडर भी बना रही हैं और मार्केट की तलाश में है।

बुरहानपुर के प्रवीण पाटिल अच्छे मुनाफे से खुश हैं। उनके पास दापोरा गांव में 60 एकड़ जमीन है, जो बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 16 किमी दूर है। दापोरा एक ग्राम पंचायत है जिसमें लगभग 700 घर हैं। उन्होंने केले की खेती का गुर अपने पिता और दादा से सीखा।

प्रवीण बताते हैं कि पिछले दो सीजन में बाजार भाव अच्छा रहा। बाजार की मांग के अनुसार 2,000 से 2,500 प्रति क्विंटल तक केला बिका। हर सीजन अच्छा नहीं रहता। कई बार मांग और आपूर्ति में भारी अंतर होता है।

यह लगभग प्रति पौधा 140 रु. तक आती है। वे बताते हैं कि 300 से 500 पौधे लगाते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो 450 से 500 क्विंटल तक उत्पादन होता है। बुरहानपुर केले का घरेलू बाजार अच्छा है। यहां से केला नई दिल्ली और हरियाणा तक जाता है। मैं उन लोगों के संपर्क में भी रहता हूं जो कृषि निर्यात करते हैं।

बुरहानपुर से 19 किमी दूर इच्छापुर गांव है जहां केले की खेती करने वाले किसानों की संख्या काफी है। अधिकतर किसान पारंपरिक खेती करते हैं। यहां के 37 वर्षीय किसान राहुल चौहान के पास 25 एकड़ जमीन है। वे बचपन से ही केले की खेती के तौर तरीकों से परिचित हो गये थे।

राहुल बताते हैं कि हम 8/5 फीट जगह में पौधे लगा रहे हैं। प्रति एकड़ 1,200 पौधे लगाते हैं। पहले 1,800 पौधे प्रति एकड़ लगा रहे थे। प्रति पौधे की लागत लगभग 150 रुपये तक आती है। एक एकड़ में 1.5 लाख का शुद्ध मुनाफा हो जाता है। एक सीजन का लाभ 25 लाख रुपये तक पहुंच जाता है। इसमें खेती की लागत भी शामिल है। एक एकड़ खेती की लागत लगभग रुपए 70 हजार तक आ जाती है। एक विकसित पौधा 15 किलोग्राम से 20 किलोग्राम तक के गुच्छे देता है।

जिला मुख्यालय से 11 किमी दूर शाहपुर गांव के राजेंद्र चौधरी जैसे छोटे किसान भी बहुत संख्या में हैं। उनके पास चार एकड़ जमीन है जिस पर वह 5000 पौधे लगाते हैं। वे औसतन 5 लाख रूपये कमा लेते हैं।

केला चिप्स इकाईयों को मिल रहा बढ़ावा

केले के उत्पादन ने केला चिप्स प्रसंस्करण इकाइयों को जन्म दिया है। फिलहाल बुरहानपुर में ऐसी 30 इकाइयां हैं। योगेश महाजन केले के चिप्स बनाने की इकाई मारुति चिप्स चलाते हैं। उनका सालाना टर्नओवर 20 से 25 लाख रुपए है। उनका कहना है कि केले की आसान उपलब्धता और लगातार आपूर्ति ने उन्हें चिप्स बनाने की इकाई खोलने के लिए प्रेरित किया। वे किसानों से सीधी खरीद करते हैं। खरीद दर फसल की आवक के अनुसार बदलती रहती है। खेतों से सीधे खरीद की दर 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्रोसेसिंग के बाद एक किलो चिप्स के पैक की थोक दर 150 रुपये है जबकि बाजार में खुदरा कीमत 200 रूपये प्रति किलो है। बाजार के बारे में उनका कहना है कि केला चिप्स अपनी गुणवत्ता के कारण पसंद किये जाते हैं। चिप्स की गुणवत्ता स्वच्छता, तलने की तकनीक, गुणवत्तापूर्ण खाद्य तेल का उपयोगए कुरकुरेपन पर निर्भर करती है। बुरहानपुर केले के चिप्स अब अपनी पहचान बन चुके है। बुरहानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर एक जिला.एक उत्पाद पुरस्कार.2023 में स्पेशल मेंशन श्रेणी का पुरस्कार मिल चुका है।

क्या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से बढ़ रहा जलसंकट, उपजाऊ जमीन हो रही बंजर?

जिस तरह से दुनिया जल संकट की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि विश्वभर में साल 2025 तक कई देश जल संकट की परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं।

भारत में 9.64 करोड़ क्षेत्र में मरुस्थलीकरण हो रहा ह, जो भारत के कुल भूमि क्षेत्र का 30 फीसदी हिस्सा है। देखा जाए तो आने वाले दिनों में मरुस्थलीकरण काफी बड़ी समस्या बन सकती है। यह संयुक्त राष्ट्र के इस अनुमान से समझा जा सकता है कि साल 2025 तक दुनियाभर के दो.तिहाई लोग जल संकट की परिस्थितियों से जूझ सकते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण के चलते विस्थापन बढ़ेगा और 13 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है।संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक विश्व भर के कुल क्षेत्रफल का करीब 20 फीसद भूभाग मरुस्थलीय के रुप में है। जबकि वैश्विक क्षेत्रफल का करीब एक तिहाई भाग सूखाग्रस्त भूमि के रूप में है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गहन खेती के कारण 1980 से अब तक धरती की एक चौथाई उपजाऊ भूमि नष्ट हो चुकी है और दुनिया भर में रेगिस्तान का दायरा निरंतर विस्तृत हो रहा है इस कारण आने वाले समय में कई चीजों की कमी हो सकती है। विश्व भर में करीब एक सौ तीस लाख वर्ग किलोमीटर भूमि मानवीय क्रियाकलापों के कारण रेगिस्तान में बदल चुकी है। प्रति मिनट करीब 23 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में तब्दील हो रही है। इस कारण खाद्यान्न उत्पादन में प्रतिवर्ष दो करोड़ टन की कमी आ रही है। दुनिया के दो तिहाई हिस्से में भू क्षरण की समस्या गंभीर हो गई है। इस कारण कृषि उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, सूखे तथा प्रदूषण की चुनौती भी बढ़ रही है। भूमि में प्राकृतिक कारणों तथा मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक या आर्थिक उत्पादन में कमी की स्थिति को भू.क्षरण कहा जाता है। जब यह अपेक्षाकृत सूखे के क्षेत्र में घटित होता हैए तो तब इसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। दरअसल इस समय पूरी दुनिया में धरती पर सिर्फ30 फीसदी हिस्से में ही वन शेष बचे हैं और उसमें से भी प्रतिवर्ष इंग्लैंड के आकार के बराबर हर साल नष्ट हो रहे हैं दुनिया भर में लोगों के लिए खाने.पीने की समुचित उपलब्ध बनाए रखने की खातिर भू.क्षरण रोकना और नष्ट हुई उर्वरक भूमि को उपजाऊ बनाना आवश्यक है।चीन ने अपने एक बहुत बड़े रेगिस्तान के क्षेत्र को 30 सालों में हरे.भरे मैदान में बदलकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कीण् जहां तक भारत का सवाल है, यहां मरुस्थलीकरण बड़ी समस्या बनता जा रहा है। मरुस्थली क्षेत्र विस्तार भूक्षरण और सूखे पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र के एक उच्च स्तरीय संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि भारत अगस्त 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षरित भूमि को उपजाऊ बनाने की दिशा में अग्रसर है जिससे ढाई से तीन अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन अवशोषित किया जा सकेगा। भू क्षरण से फिलहाल भारत की करीब 30 फीसदी भूमि प्रभावित है, जो बेहद चिंताजनक है। पर्यावरण क्षति की भरपाई के प्रयासों के तहत पिछले एक दशक में करीब 300000 हेक्टेयर वन क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

संपादकीय

भारत ने जून 2019 में परीक्षण के तौर पर पांच राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रए नगालैंड, कर्नाटक में वनाच्छादित क्षेत्र बढ़ाने की परियोजना शुरू की थी और अब इस परियोजना को धीरे.धीरे मरुस्थलीकरण से प्रभावित अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। प्रकाशित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि देशभर में 9.64 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में मरुस्थलीकरण हो रहा है, जो भारत के कुल भूमि क्षेत्र का करीब 30 फीसदी हिस्सा है। इस क्षरित भूमि का 80 फीसदी हिस्सा केवल 9 राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और तेलंगाना में है। दिल्ली, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया काफी तेज है।

भारत के कई राज्यों जैसे कि झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और गोवा के लगभग 50 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सों में क्षरण हो रहा है। बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से मरुस्थलीकरण अर्थात उपजाऊ जमीन के बंजर बन जाने की समस्या विकराल हो रही है। सूखे इलाकों में जब लोग पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन करते हैं तो वहां पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं और उस क्षेत्र की जमीन बंजर हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता का बढ़ावा दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में मरुस्थलीकरण रोकथाम का प्रस्ताव रखा था। भारत में उस पर 14 अक्टूबर 1994 को हस्ताक्षर किए। देश के थार मरुस्थल ने उत्तर भारत के मैदानों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। चिंताजनक स्थिति यह है कि थार के मरुस्थल में प्रतिवर्ष 13000 एकड़ से भी अधिक बंजर भूमि को वृद्धि हो रही है।

हर चौथे साल फरवरी में क्यों होते है 29 दिन, जानिए, क्यों कहा जाताहै लीप ईयर

हलधर किसान
88174 02860

इस साल फरवरी में 28 के बजाय 29 दिन होंगे। सामान्य तौर पर इस वर्ष को लीप ईयर कहा जा रहा है। लीप वर्ष उन लोगों के लिए जश्न का साल होता है, जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ हो, लेकिन, यह कैसे पता चलता है कि किस साल को लीप ईयर माना जाता है। क्या इससे लोगों के जीवन पर कोई असर पड़ सकता है? वैसे तो साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन चार साल में एक बार साल में 366 दिन भी होते हैं। इसे ही लीप ईयर कहा जाता है। साल का ये अतिरिक्त दिवस फरवरी माह में जोड़ा जाता है। इसी वजह से फरवरी माह आम तौर पर 28 और लीप वर्ष में 29 दिन का होता है।

फरवरी माह में ग्रहों में बदलाव की स्थिति भी बनने वाली है। इस बदलाव का राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इसके बाद में अमजेर के ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन का कहना है कि ग्रहों की बदलती चाल हमारे जीवन पर कई प्रभाव डालती है, कुछ सकारात्मक होते हैं तो कुछ का प्रभाव नकारात्मक भी होता है। साल 2024 की शुरुआत में ही कई ग्रहों का गोचर देखने को मिला, जिससे कुछ राशि के जातकों को तो फायदा हुआ, लेकिन कुछ राशि के जातकों को थोड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में अगर आप भी उनमें से एक है जिन्हें जनवरी के महीने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो फरवरी के महीने में कौन सा बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है और इसका प्रभाव किन राशियों पर पड़ेगा, आईये जानते है।

फरवरी माह में सबसे बड़ा गोचर 1 फरवरी 2024 को देखने को मिलेगा। जब बुध देव अपनी चाल बदलेंगे और मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में बुध ग्रह का गोचर किन राशि के जातकों पर प्रभाव डालेगा ।

मेष राशि:. मेष राशि के जातकों पर बुध देव का मकर में गोचर शुभ साबित होगा, इतना ही नहीं इस राशि के जातकों को गुप्त शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी।

मिथुन राशि:. मिथुन राशि के जातकों के लिए भी बुध का मकर राशि में गोचर लाभकारी होने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, इसके अलावा अगर किसी भी तनाव से आप गुजर रहे हैं, तो वह दूर होगा और सुख.सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।

कर्क राशि:. बुध ग्रह का मकर राशि में गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए भी फलदायी होगा। ज्योतिषों के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के मान.सम्मान में वृद्धि होगी और उन्हें सुख सुविधाओं का फल मिलेगा।

सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए भी बुध का गोचर अनुकूल साबित हो सकता है, इस दौरान बुध राशि के जातक नई भूमि या गाड़ी में इन्वेस्ट कर सकते है, उनकी लैविश लाइफ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और कई नए काम की शुरुआत के साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

प्रपोज डे से क्या है कनेक्शन?

2024 पिछले तीन सालों से खास रहने वाला है। वजह है कि यह साल लीप ईयर होगा। लीप ईयर यानी 365 की जगह साल में 366 दिन होंगे, समय के साथ 29 फरवरी सिर्फगणित का जोड़-तोड़ नहीं रह गया है। दुनियाभर में इस दिन को लेकर कई रीति-रिवाज भी बने। इसका प्रपोज डे से क्या है कनेक्शन? दिलचस्प बात है कि ज्यादातर रिवाज रोमांस और शादी से संबंधित हैं, बताया जाता है कि आयरलैंड में 5वीं सदी में सेंट ब्रिजेट ने सेंट पैट्रिक से कहा था कि महिलाओं को पुरुषों के सामने शादी का प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं है, तब सेंट पैट्रिक ने 29 फरवरी को एक ऐसे दिन के रूप में नामित किया, जिस दिन महिलाओं को पुरुषों को प्रपोज करने की अनुमति होगी। कुछ जगह लीप डे को बैचलर डे के रूप में जाना जाता है।

स्कॉटलैंड की रानी ने इस रिवाज में महिलाओं के फायदे के लिए एक नया ट्विस्ट जोड़ा,इसमें कहा गया था कि महिलाएं हर 29 फरवरी को प्रपोज कर सकती हैं और अगर कोई पुरुष इनकार करता है, तो उसे महिला को जुर्माने के रूप में नया गाउन, दस्ताने या चुंबन देना होगा।

किसने सुधारा था कैलेंडर?

लीप ईयर जोड़ने की शुरूआत हजारों सालों पहले रोमन जनरल जुलियस सीज़र ने की थी। तब रोमन कैलेंडर 355 दिनों का ही हुआ करता था। उस समय दिसंबर की जगह फ़रवरी साल का आखिरी महीना था। सीज़र ने आदेश दिया कि हर चार साल बाद साल के आखिरी दिन में 24 घंटे जोड़े जाएं, इससे चार साल के अंतराल में 24 फ़रवरी, तब का साल का आखिरी दिन, का दिन 24 की जगह 48 घंटों का होने लगा। मगर यह भी सटीक गणित नहीं थी और धीरे.धीरे कैलेंडर में अनियमितता बढ़ने लगी।

16वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च ने कैलेंडर में आखिरी बड़ा बदलाव किया। चर्च ने यह जिम्मा इसलिए भी उठाया क्योंकि कैलेंडर की त्रुटि की वजह से ईस्टर (ईसाईयों का महत्वपूर्ण वार्षिक धार्मिक पर्व) की तारीख अपने पारंपरिक स्थान से लगभग दस दिन दूर हो गई थी। पोप ग्रेगरी ग्ण्प् ने एक संशोधित कैलेंडर शुरू किया, जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। इसमें 400 से विभाजन होने वाले सालों को लीप ईयर माना जाता है। इस वजह से सन् 1800- 1900 लीप ईयर नहीं थे, लेकिन सन् 2000 लीप ईयर था।

विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रेगोरियन गणना भी बिल्कुल सटीक नहीं है। इस वजह से कैलेंडर में एक और बदलाव होना जरूरी है, हालांकि, इस कैलेंडर की गणना हर 3,030 साल में केवल एक दिन के हिसाब से गलत है। इसलिए कैलेंडर को अपडेट करने के लिए हमारे पास काफी समय है।

लीप ईयर में 366 दिन होना क्यों जरूरी?

पहले समझते हैं कि लीप डे की जरूरत क्यों होती है। हमारी पृथ्वी सौर मंडल में सूरज के चक्कर लगा रही है, जब पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हो जाता है, तो उसे धरती का एक साल कहते हैं। अब इस एक चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड्स लगते हैं। मोटे तौर पर एक साल को 365 दिन लंबा माना जाता है, लेकिन इस अतिरिक्त 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड्स को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर इस समय की गणना नहीं की जाएगी तो फ़सल का चक्र और मौसम धीरे.धीरे साल के अलग.अलग समय पर होने लगेंगे। एक समय ऐसा भी हो सकता है जब जनवरी में गर्मी और सितंबर में तेज धूप निकलने लगे। इस एक दिन को जोड़ने से लोगों को सहूलियत होती है।

बाएं से दाएं

1. स्वीकारोक्ति, जी (1)
6. हर काम को जानने वाला (6)
7. जाने का आदेश देना, दुत्कारना, बोलचाल (1)
8. विष्णु का एक अवतार (3)
10. बुरी आदत (3)
11. प्रतिष्ठा जाती रहना, मुहावरा (5)
15. करीब.करीब (4)
16. अपमान (5)
18. बच्चों का छोटा झूला (3)
19. हाथ की एक उँगली का नाम (4)

ऊपर से नीचे

2. तरणताल आदि में विचरण करना (3)
3. सहमति होना (5)
4. निमंत्रण (3)
5. नाच (3)
9. अधिकार (2)
12. हिचकना, बेचैन होना(5)
13. क्रोध या ईर्ष्या भड़काना , मुहावरा (5)
14. घर के भीतर का खुला भाग (3)
17. जल का स्रोत, सरिता (2)

वर्ग पहेली

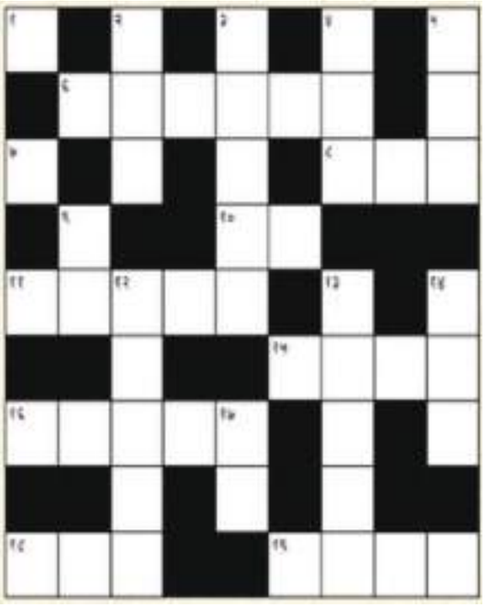

द गैडवाल

इन मंदिरों की शानदार वास्तुकला के पर्यटक हो जाते हैं कायल

हलधर किसान

इंदौर। हर मंदिर का अपना अलग अध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। लेकिन भारत देश के अलग.अलग हिस्सों में फैले कई मंदिर ऐसे भी हैं, जो धार्मिक महत्व के साथ.साथ अपनी शानदार वास्तुकला और ऐतिहासिकता के कारण दूर.दराज के इलाकों से भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हाल ही अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन काफी चर्चाओं में रहा।

मंदिर के ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के साथ.साथ इस मंदिर की शानदार वास्तुकला भी लोगों में चर्चा का विषय बन गयी। हम यहां कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जहां आने वाले श्रद्धालु सिर्फ इसके धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि शानदार वास्तुकला के भी कायल होते हैं। राम मंदिर,उत्तर प्रदेश अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर बना राम मंदिर दुनियाभर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हालांकि अभी तक इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में मंदिर के प्राण- प्रतिष्ठा समारोह के बाद राम मंदिर के अंदरुनी हिस्सों की जो तस्वीरें शेयर की गई हैं, उनको देखकर ही समझ में आ रहा है कि यह शानदार वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस मंदिर का निर्माण पूरी तरह से पत्थरों से किया गया है। पत्थरों को तराशकर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां और देवी.देवताओं की मूर्तियों को मंदिर की दिवारों पर उकेरा गया है। कहा जा रहा है कि नागर शैली में बना राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। जनवरी 2024 में इसका गर्भगृह तथा प्रथम तल बनकर तैयार है और 22 जनवरी 2024 को इसमें श्रीराम के बाल रूप में विग्रह की प्राणप्रतिष्ठा की गई। राम मंदिर का मूल डिज़ाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है।

श्रीराम मंदिर अयोध्या

अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली

अक्षरधाम मंदिर: नई दिल्ली में बना स्वामिनारायण अक्षरधाम मन्दिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामिनारायण की पुण्य स्मृति में बनवाया गया है। इसके मुख्य देव भगवान स्वामीनारायण है। यह परिसर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मन्दिर परिसर होने के नाते 26 दिसम्बर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफवर्ल्ड रिकार्ड्स में शामिल किया गया। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को देखकर ही समझ में आता है कि यह एक ऐसा आधुनिक समयकाल में बना मंदिर है, जो पूरी तरह से प्राचिन भारतीय कला और वास्तुकला से प्रेरित है। साल 2005 में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। उसके बाद से लेकर आज तक में, यह मंदिर भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक बना हुआ है जहां सबसे अधिक लोग जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर ही मंदिर के खंभों से लेकर शिखर और मूर्तियों को तराशा गया है।

मीनाक्षी अम्मन मंदिर: दक्षिण भारतीय के सभी मंदिर ही अपनी शानदार वास्तुकला के कारण पूरे देश से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तमिलनाडु मदुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर भी इससे अलग नहीं है। यह मंदिर द्रविड़ियन शैली का शानदार उदाहरण है। सिर्फमंदिर परिसर ही नहीं बल्कि इसके गोपुरम में भी उकेरी गयी कलाकृतियों को देखकर किसी के भी पांव बस ठहर जाएंगे। इस मंदिर में काफी चटकिले रंगों का इस्तेमाल कर इन कलाकृतियों में तो मानों जान ही फुंक दी गयी है।पारंपरिक पौराणिक मान्यताओं के आधार मंदिर के हर एक स्तंभ पर कलाकृतियों को उकेरा गया है जो इस मंदिर की प्रमुख खासियतों में शामिल है।

यह हिन्दू देवता शिव (सुन्दरेश्वरर) या सुन्दर ईश्वर के रूप में एवं उनकी भार्या देवी पार्वती (मीनाक्षी या मछली के आकार की आंख वाली देवी के रूप में) दोनो को समर्पित है। यह ध्यान योग्य बात है कि मछली पांड्य राजाओं का राजचिह्न था। यह मन्दिर तमिल भाषा के गृहस्थान 2500 वर्ष पुराने मदुरई नगर1,ए की जीवनरेखा है। हिन्दु पौराणिक कथानुसार भगवान शिव सुन्दरेश्वरर रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राजा मलयध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरई नगर में आये थे। मीनाक्षी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। इस मन्दिर को देवी पार्वती के सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है।

खजुराहो मंदिर (मप्र): खजुराहो मंदिर समुह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। 9वीं से 11वीं सदी के बीच चंदेल राजवंश द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। खजुराहो मंदिर अपनी कामुक नक्काशी की वजह से सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, जो मनुष्य के जीवन और अध्यात्म को एक धागे में पिरोता है। इस समुह का सबसे बड़ा मंदिर भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर है। कहा जाता है कि 12वीं सदी तक खजुराहो में 85 मंदिर थे। जब 13वीं शताब्दी के दौरान, मध्य भारत पर दिल्ली सल्तनत ने कब्जा कर लिया, तो कुछ मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और बाकी को उपेक्षित छोड़ दिया गया। जिसके बाद यहां पर केवल 22 मंदिर ही बच पाए।

खजुराहो मंदिर, मप्र

कोणार्क का सूर्य मंदिर (ओडिसा)। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग वास्तुकला के आधार पर किया गया था। भगवान सूर्य को समर्पित इस मंदिर की आकृति किसी रथ के समान ही है। लेकिन यह लकड़ी से बना कोई रथ न होकर भारी.भरकम पत्थरों को तराशकर बनाया गया एक विशाल रथ की आकृति वाला मंदिर है। इस मंदिर की खासियत सिर्फइसकी वास्तुकला ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग भी है। इस मंदिर में सूर्य के आधार पर समय और तारीख का पता लगाने जैसी कई घड़ियां भी मौजूद हैं, जिन्हें पत्थरों को तराशकर ही तैयार किया गया है।कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है।

इसका निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी (1238.1264 ई) में किया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य, मज़बूती और स्थिरता के साथ.साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। यह सूर्य भगवान को समर्पित है। इस अर्थ में यह सीधे भौतिक रूप से ब्राह्मणवाद और तांत्रिक विश्वास प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। कोणार्क के मंदिर न केवल अपनी स्थापत्य की भव्यता के लिये बल्कि मूर्तिकला कार्य की गहनता और प्रवीणता के लिये भी जाना जाता है। यह कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु है जो अनुग्रह, खुशी और जीवन की लय को दर्शाता है। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

सूर्य मंदिर कोणार्क

यह मंदिर भी अपनी अनोखी कलाकृति के लिए है विश्व प्रसिद्ध

भारत में प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक शांति को पाने के लिए कई तरह के मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। यहां के हर राज्य में विभिन्न मंदिर स्थित है। इनमें से कुछ बेहद ही प्राचीन है और उनका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। ये मंदिर भारतीय संस्कृति और जीवन शैली की विविधता को दर्शाते हैं। भारत में मंदिर वास्तुकला ने हमेशा अनुभव, स्थान और समय का प्रतिनिधित्व का किया है।

बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु तंज़ौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वरा मंदिर के नाम से भी जाता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल एक ऐतिहासिक मंदिर है।

कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफाएं: महाराष्ट्र एलोरा की गुफाओं में एकलौते पत्थर को तराशकर विशाल कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, जो इस बात को साबित करता है कि प्राचिन काल में भारत की वास्तुशिल्पकला कितनी उन्नत थी। भगवान शिव के इस मंदिर की दिवारों पर हिंदू धर्म के आधार पर विभिन्न देवी.देवताओं की आकृतियों को उकेरा गया है।

2 फरवरी से 31 मार्च तक आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, जानिए कैसे करें बुकिंग

95 साल पुराना है अमृत उद्यान का इतिहास, स्वर्ग सा कराता है एहसास

हलधर किसान 88174 02860

नई दिल्ली. रंग.बिरंगे फूलों की खूबसूरती के कारण देश-दुनिया में मशहूर अमृत उद्यान (मुगल गार्डन) आज जनता के लिए खुलने जा रहा है। समृद्ध इतिहास और विरासत की कहानियों को संजोये यह उद्यान राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाता है। इस वर्ष, उद्यान उत्सव.के तहतआम लोगों के लिए 2फरवरी से 31 मार्च तक खोला जायेगा। अगर मौका मिले तो इस खूबसूरत उद्यान की सैर जरूर कीजियेगा।

नई दिल्ली के इस खुबसुरत उद्यान में आम जनता के लिए भ्रमण 2 फरवरी से 31 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में सप्ताह के छह दिन सोमवार को छोड़कर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। आगंतुकों को ऑनलाइन या वॉक.इन बुकिंग के माध्यम से भ्रमण के लिए पंजीकरण करना होगा। आप चाहे तो बिना ऑनलाइन बुकिंग के भी जा सकते हैं लेकिन तब आपको लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। वॉक.इन बुकिंग के लिए आगंतुकों को सुविधा केंद्रों या राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 12 के पास स्व.सेवा केंद्र पर अपना पंजीकरण करना होगा। सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा, जहां नॉर्थ एवेन्यू राष्ट्रपति भवन से मिलता है। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा सुबह 9. 30 बजे से शाम 5. 00 बजे तक हर 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होगी। भ्रमण के दौरान आगंतुक बोनसाई उद्यान, संगीतमय फव्वारा, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन देख सकेंगे। निकास स्थान पर उनके लिए फूड कोर्ट उपलब्ध होंगे।

कैसे करें अमृत उद्यान के टिकट की बुकिंग

rashtrapatibhavan.gov.in/visit/amrit-udyan/rE खोलें, साइड खुलने पर दाहिनी ओर ऊपर बुक नॉ बटन पर क्लिक करें। जिस दिन आप जाना चाहते हैं उसकी तिथि व समय का चयन करें। अकेले या परिवार या मित्रों के साथ, कॉर्पोरेट ग्रुप या स्कूल ट्रिप में से किसी एक विकल्प पर क्लिक करें। उम्र के हिसाब से लोगों की संख्या भरें। ओटीपी के लिए आपना मोबाइल नंबर लिखें। ओटीपी आने पर वैरिफिकेशन के लिए उसमें लिखें। अगले पेज में आपको अपना नाम, राज्य, जिला और कौन सा पहचान पत्र साथ ले जा रहे हैं वो लिखना होगा। इसके बाद कंन्टीन्यू पर क्लिक करते ही आप रिव्यू पेज पर जाएंगे। फिर आगे बढ़ें। रिव्यू करने के बाद कंटीन्यू पर क्लिक करें। चूंकि अमृत उद्यान का कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, इसलिए बिना फिस के आपकी बुकिंग सुनिश्चित हो जाएगी। ध्यान रहे जिस पहचान पत्र को आपने यहां लिखा है, वहां जाने पर वही पहचान पत्र साथ रखियेगा।

उद्यान दो स्लॉट में सुबह 10 बजे से 12बजे तक और दोपहर में 12 से 4बजे तक अलग.अलग आगंतुक क्षमता के साथ खुला रहेगा। सप्ताह के दिनों में सुबह के स्लॉट में 7,500 और दोपहर में 5,000 लोग आ सकते हैं। वहीं सप्ताहांत में क्रमशः 10,000 और 7,500 लोगों को प्रवेश दिया जा सकता है। सुविधाजनक पहुंच और सुविधाएं सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आपकी यात्रा न केवल शैक्षणिक हो बल्कि आरामदायक भी हो। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक हर 30 मिनट में एक शटल बस सेवा संचालित होती है, जिससे आपकी अमृत उद्यान तक की यात्रा आसान हो जाती है। एक बार अंदर जाने पर, आपको बोनसाई गार्डन, म्यूजिकल फाउंटेन और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आने वाले परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक सड़क के किनारे फूड कोर्ट, पीने के पानी की सुविधाएं, शौचालय और चिकित्सा सहायता रणनीतिक रूप से रखी गई हैं। माता.पिता बच्चों के लिए मोबाइल फोन, पानी की बोतलें और दूध की बोतलें जैसी आवश्यक वस्तुएं ला सकते हैंए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यात्रा के दौरान छोटे बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की जा सके।

विशेष श्रेणियों के लिए भ्रमण तिथियां तय

विशेष श्रेणियों के आंगुतको के लिए तिथियां तय की गई है, इनमें 22 फरवरी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, 23 फरवरी रक्षा, अर्धसैनिक और पुलिस बलों के कर्मचारियों के लिए, 1 मार्च महिलाओं और आदिवासी महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए और 5 मार्च को अनाथालयों के बच्चों के लिए व्यवस्था होगी।

15 एकड़ में फैला है गार्डन

अमृत उद्यान अपने रंग.बिरंगे फूलों की खूबसूरती के कारण देश दुनिया में मशहूर है, वहीं, 15 एकड़ में फैले इस गार्डन में आपको 159 किस्म के गुलाब, ट्यूलिप समेत तमाम प्रकार के फूल और पौधे दिख जाएंगे। इस गार्डन में आप सप्ताह के 6 दिन घूमने जा सकते हैं। यह सोमवार को बंद रहता है। रंग.बिरंगे फूलों और अमृत उद्यान के सौंदर्य को देखने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग दिल्ली आते हैं। अगर आपको भी अपने बच्चे और दोस्तों के साथ दीदार करना है, तो फटाफट तैयारी कर लीजिए। अमृत उद्यान का डिजाइन ताजमहल के बगीचों, जम्मू.कश्मीर के बगीचों से प्रेरित है और इसी वजह से इसका नाम मुगल गार्डन पड़ा था। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में वास्तुकला की भारतीय और पश्चिमी दोनों ही शैलियां हैं, इसी आधार पर अमृत उद्यान को तैयार किया गया था। सर लुटियंस ने यहां पर मुगल शैली और अंग्रेजी फूलों को एक साथ लाकर खूबसूरत उद्यान बनाया। देश के हर एक राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन की संपना में अमूल्यनीय योगदान रहा है। ऐसे ही राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने हर्बल उद्यान, टैक्टाइल उद्यान, म्यूजिकल उद्यान, बायो.फ्यूल पार्क, आध्यात्मिक और पोषण उद्यान आदि का महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

परखें कृषि ज्ञान, आसान सवालों का जवाब देकर पाएं आकर्षण उपहार

हलधर किसान से जुड़े पाठको के लिए हम लाए है कृषि से जुड़े आसान सवाल, जिनके जवाब देकर आप अपना सामान्य ज्ञान परखने के साथ ही पा सकते है आकर्षक उपहार, तो इस अंक में भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपुर्ण प्रश्नों के दीजिए उत्तर-

प्रश्न. भारत में कौन- सा कृषि वित्त का स्त्रोत नही हैं?

अ. सहकारी समितियां
ब. व्यापारिक बैंक
स. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
द. उपरोक्त में से कोई नहीं

आपका जवाब .....

प्रश्नः- निम्न में से कौन- सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता हैं ?

अ. कुशल सिंचाई
ब. कीटनाशकों का उपयोग
स. उर्वरकों का प्रयोग
द. उपरोक्त में से कोई नहीं

आपका जवाब.....

प्रश्नः- भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?

अ. केरल
ब. कर्नाटक
स. तमिलनाडू
द. मेघालय

आपका जवाब .....

प्रश्नः- भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान?

अ. बढ़ रहा है।
ब. घट रहा है।
स. स्थिर है।
द. उपरोक्त में से कोई नहीं

आपका जवाब.....

जनवरी माह के सवालो का सही जवाब, सवाल 1-द, सवाल 2 -ब, सवाल 3-स, सवाल 4 का उत्तर- द है।

नोटः आपके जवाब हमें इस प्रश्नोत्तरी में दर्ज कर अखबार की कटिंग 25 नवंबर तक हमारे वाट्सएप्प नंबर (88174 02860) पर, या हमारे मुख्य कार्यालयः हमारे प्रधान कार्यालय 598, वेगॉस मॉल, कार्पोरेट बिल्डिंग, एस.14 द्वारका साउथ वेस्ट, नई दिल्ली 110075 या मप्र में 762, बीज भंडार भवन, न्यू नूतन नगर खरगोन में संपर्क कर सकते है। पर डाक के जरिये भेज सकते है। सही जवाब देने वाले पाठको का लॉटरी के जरिये परिणाम निकाला जाएगा। सही जवाब देने वाले विजेता को हलधर किसान की ओर से आकर्षण उपहार उनके भेजे गए पते पर भेजे जाएंगे। अगले अंक में हम सही जवाब और विजेता का नाम घोषित करेंगे।

ई- मेल - (haldharkisankgn@gmail.com) पर भी भेज सकते है।

समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 05 फरवरी से होगा किसानों का पंजीयन

भोपाल। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने तथा बिचौलियों व दलालों के शोषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा रबी सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के इंतजाम किये है। विपणन वर्ष 2024.25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 05फरवरी से 01 मार्च 2024 तक जिले की सहकारी समितियों, एम.पी ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर एवं किसान ऐप के माध्यम से किसान पंजीयन कराया जायेगा। किसानों से पंजीयन केन्द्रों में निर्धारित समयावधि में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराने की अपील की गई है।

मिली जानकारी अनुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालयए एवं तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र, सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर किसानों का निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा। इन केन्द्रों पर किसान प्रातः 07 बजे से रात्रि 09 बजे तक शासकीय कार्य दिवसों में अपना पंजीयन करा सकते हैं। किसान अपने एन्ड्रायड मोबाइल से एमपी किसान एप के माध्यम से निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। एमपी ऑनलाइन कियोस्कए कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित सायबर कैफे पर सशुल्क पंजीयन की व्यवस्था है।

जनवरी माह के अंक की प्रश्नोत्तरी के विजेता को पुरस्कृत करते संस्था के मार्गदर्शक एवं संरक्षक श्री विनोद जैन

देश की 199 जिला कृषि मौसम इकाइयां 29 फरवरी से बंद होंगी किसानों को नही मिल सकेगी मौसम की सटिक जानकारी

हलधर किसान

किसानों को मौसम का सटीक पूर्वानुमान, फसल संबंधी सावधानियां बताने के लिए वर्ष 2019 से संचालित जिला कृषि मौसम इकाइयां अब बंद होने जा रही हैं। देशभर के 199 कृषि विज्ञान केंद्रों में संचालित इन इकाइयों को 31 मार्च के बाद बंद कर दिया जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग ने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है। पहले इसे 31 मार्च तक बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन बुधवार को जारी पत्र में इसकी तारीख घटाकर 29 फरवरी से ही इसे बंद करने को कहा गया है। इसे लेकर किसानों में आक्रोश है।

ज्ञात हो कि विगत चार वर्षों से कृषि एवं मौसम विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जा रही थी। वहीं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 29 फरवरी 2024 से बंद करने के आदेश पारित किए हैं। जिसके तहत् कृषकों को मौसम की व कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध होना बंद हो जाएगी। खंडवा जिले में जिला कृषि मौसम इकाई की शुरुआत नवंबर 2019 से मौसम विज्ञान विभाग (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय) एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कृषि मंत्रालय) के समन्वय से हुई।

समस्याओं पर आनलाइन चर्चा करते थे किसान

जिला कृषि मौसम इकाई के विशेषज्ञ द्वारा प्रत्येक सोमवार को जूम मीटिंग एप पर किसानों के साथ पूर्वानुमान एवं फसलों की समस्याओं पर आनलाइन चर्चा भी की जाती थी। जिससे तुरंत समाधान मिलता था। जिले भर के किसानों से जिला कृषि मौसम इकाई के विशेषज्ञ मोबाइल पर चर्चा करने के लिए हर समय उपलब्ध रहते थे। जिससे क्षेत्र के किसानों को उचित जानकारी समय समय पर मिल जाती थी। इस परियोजना के द्वारा क्षेत्र के प्रत्येक गांव के किसानों तक मौसम एवं कृषि आधारित उचित सलाह मिलने से कृषि में उन्नत तकनीक व सही

कई जिलों के किसानों को मिल रहा था लाभ

इस परियोजना के द्वारा खंडवा ज़िले के किसानों के साथ ही बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, खरगोन एवं धार जिलों के किसानों को भी लाभ मिल रहा था। जिला कृषि मौसम इकाई द्वारा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को अगले पांच दिन के मौसम (वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, हवा की दिशा, बादल आवरण) की जानकारी के साथ ही मौसम आधारित कृषि सलाह पत्रक इंटरनेट मीडिया समूहों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे थे। जिससे समय रहते कृषक खेती में फसलों का उचित प्रबंधन कर लेते थे। साथ ही सटीक दवाओं की जानकारी मिलने से किसानों की लागत भी कम होती थी।

आकस्मिक आपदाएं आने से तेज आंधी.तूफान के साथ वर्षा होना, ओले गिरनाए आकाशीय बिजली गिरना आदि की जानकारी विभाग द्वारा किसानों को व्हाट्स एप के माध्यम से 48 से 72 घंटों पहले मिल जाती थी। जिससे समय रहते किसानों को फसलों के साथ ही पशुधन एवं जन.धन में होने वाली हानि को कम करने में मदद मिल पाती थी।

दवाओं के सही समय पर उपयोग करने के कारण किसानों की कृषि लागत काफी कम होने के साथ ही उत्पादन में भी बढ़ोतरी होना संभव हो पाया है। इस उपयोगी परियोजना को मौसम विज्ञान विभाग (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय) द्वारा 31 मार्च 2024 को बंद करने का आदेश निकाल दिया है। जिससे किसान वर्ग में रोष हैं।

- इस संबंध में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है। मौसम की जानकारी किसानों को 29 फरवरी के बाद नहीं मिल पाएगी। पहले 31 मार्च तक इसे बंद करने के लिए कहा गया था लेकिन अब 29 फरवरी को बंद करने के निर्देश मिले हैं।- .डा. सौरभ गुप्ता, कृषि एवं मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, खंडवा।

रीवा वन विभाग ने कि सेंसर आधारित स्मार्ट प्लांटेशन मॉनिटरिंग कि शुरुआत

पौधारोपित क्षेत्रों में नमी के स्तर की निगरानी रखेगा सेंसर

हलधर किसान. रीवा।

वन विभाग ने सेंसर आधारित स्मार्ट प्लांटेशन मॉनिटरिंग की शुरुआत की है। बताया गया कि पूरे देश में वन विभाग का ये पहला ऐसा प्रयास है। वन विभाग की ओर से डीएफओ आलोक शर्मा ने बताया कि वन विभाग हर साल कई जगहों पर पौधे लगाता है। पर वन विभाग के काम में सबसे बड़ी चुनौती पौधों को जीवित रखने की होती है। पौधों की जीवितता जिन चीजों पर निर्भर करती है वो है उचित मात्रा और समय पर पानी की सिंचाई।

अत्याधिक पानी, अत्याधिक सूखा या अधिक देरी पर पानी देना ये सभी चीजें पौधों के लिए नुकसानदायक होती हैं। हर रोज इस पर नजर रखना भी काफी कठिन होता है। जिसके लिए अब रीवा वन विभाग ने स्मार्ट सेंसर के माध्यम से पौधारोपण क्षेत्रों में नमी के स्तर की निगरानी शुरू कर दी है। ऐसा करने से रीवा पूरे देश में पहला वनमण्डल बन गया है।

मिट्टी की नमी की रियल टाइम मॉनिटरिंग

प्रारंभिक तौर पर रोपण क्षेत्रों में मिट्टी की नमी की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। अगर प्रयोग सफल और उपयोगी रहा तो अन्य तरह के सेंसर (जैसे पीएचए उर्वरकता) भी लगाए जाएंगे। अभी यह सिस्टम बसामन मामा गौवंश विहार में रीवा वन विभाग द्वारा किए गए ब्लॉक पौधारोपण में और रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के नगर वन में लगाया गया है।

इस तरह काम करता है पूरा सिस्टम

पूरा सिस्टम सौर ऊर्जा से संचालित रहता है। मतलब, इसके संचालन के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। सेंसर्स को सैंपल पौधों की जड़ों के पास मिट्टी में स्थापित किया जाता है। ये सेंसर्स मिट्टी की नमी की स्थिति डाटा लॉगर में भेजते हैं। डाटा लॉगर से नमी की मात्रा की जानकारी इंटरनेट क्लाउड पर जाती है। हर घंटे का डाटा रिकॉर्ड होता रहता है।

इस डाटा को अधिकारी कहीं पर भी, किसी भी समय देख सकते हैं और आवश्यकता समझ आने पर वन अमले को पौधों की सिंचाई हेतु निर्देशित कर सकते हैं।

गेंहू एवं जौ के लिए बेहद खतरनाक है चेपा किट

हलधर किसान (रबी सीजन)।

गेंहू एवं अन्य रबी फसलों में बदलते मौसम के चलते खरपतवार, चेपा कीट की दिक्कतें सामने आती है। यदि समय रहते इनका प्रबंधन नहीं किया जाए तो, उत्पादन पर असर पड़ता है। गेंहू की अच्छी पैदावार के लिए किसान साथियों को फसल की देखभाल करना जरूरी है। हालांकि रबी सीजन में खरपतवार प्रकोप इतना ज्यादा देखा नही जाता है।बदलते मौसम के कारण गेंहू की फसल में चेपा कि समस्या अधिक देखी जाती है।

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक चेपा किट रबी फसलों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। गेहूं व जौ में चेपा का आक्रमण अधिक देखा गया है। चेपा फसल को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है।

ऐसे में इसके बचाव के लिए हरियाणा कृषि विभाग के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जरूरी सलाह जारी की गई है।

हरियाणा कृषि विभाग के द्वारा जारी की गई सूचना के मुताबिक, चेपा गेहूं व जौ की फसलों में कीट के बच्चे व प्रौढ़ पत्तों से रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं।

क्या है चेपा किट

चेपा एक तरह का कीट होता है, जो गेहूं व जौ की फसल पर सीधे तौर पर आक्रमण करता है।अगर यह कीट एक बार पौधे में लग जाता है, तो यह पौधे के रस को धीरे.धीरे चूसकर उसे बहुत ही कमजोर कर देता है, जिसके चलते पौधा का सही से विकास नहीं हो पाता है।

देखा जाए तो चेपा कीट फसल में नवंबर से फरवरी महीने के बीच में अधिकतर देखने को मिलता है। यह कीट फसल के सबसे कोमल व कमजोर हिस्सों को अपनी चपेट में लेता है और फिर धीरे.धीरे पूरी फसल में फैल जाता है। चेपा कीट मच्छर की तरह दिखाई देता है, यह दिखने में पीले, भूरे या फिर काले रंग के कीड़े की तरह होते है। गेहूं व जौ की फसलों में चेपा का आक्रमण होने पर इस कीट के बच्चे व प्रौढ़ पत्तों से रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 500 मिली. मैलाथियान 50 ई.सी को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़काव करें। किसान चाहे तो इस कीट से अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं।

नवाचार: गोबर खाद से तैयार किया खेत, लहलहा रही गेहूं की फसल

प्रगतिशील कृषक दौलत माली ने 3 एकड़ रकबे में तैयार कि जैविक खेती

हलधर किसान /सहज और सरल तरीके से कैसे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाई जा सकती है यह राह प्रगतिशील किसान दौलत माली ने दिखाई है। उन्होंने साल दर साल कम हो रहे उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवाचार के रूप में दोबारा जैविक खेती की ओर रुख कि और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है।

श्री माली ने **हलधर किसान** को बताया कि वे 9 एकड़ रकबे में खेती करते है। भेड चाल के दौर में वे भी परंपरागत खेती छोड़कर रसायनिक की ओर चल पड़े थे। शुरुआत में अधिक उत्पादन मिलने से इसी पर आश्रित हो गए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से मौसम में आए बदलाव और मिट्टी की कम होती उपजाऊ क्षमता के चलते उत्पादन कम होने लगा था, जिसे बढ़ाने के लिए उन्होंने 3 एकड़ रकबे में रबी सीजन में खेत को गोबर खाद से तैयार कराया। इसके बाद गेहूं बीज की बुआई की। वर्तमान में फसल करीब 3 माह की हो गई है, जैविक और रसायनिक दोनो तरह की लगाई फसल में साफ अंतर नजर आ रहा है। जैविक तरीके से तैयार कि गई गेहूं फसल की बाली अधिक होने के साथ ही दाना मोटा है, जबकि रसायनिक फसल की हाईट कम होकर बाली में दाने भी कम है।

रासायनिक खाद और अन्य जहरीले रसायनों से बर्बाद हो रही खेती

श्री माली ने बताया कि रासायनिक खाद और अन्य जहरीले रसायनों के इस्तेमाल से खेती बर्बाद हो रही है। भूमि में आर्गेनिक कार्बन, मित्र सूक्ष्म जीव, मित्र फंगस और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। गोबर की विभिन्न तरह की खादों और अन्य जैविक खादों का प्रयोग लगभग न के बराबर हो रहा है। या बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अपने अनुभव का हवाला देते हुए श्री माली ने बताया कि जैविक खाद से उत्पादन पर उपज का भाव भी अधिक मिल रहा है। उन्होंने कहा जैविक खाद की ताकत किसी रासायनिक खाद से कम नहीं होती है। गोबर की खाद जिसे किसान खेतों में डालना भूल गये हैं। उसी से बनी खाद से पहाड़ी पर फसल लहलहा सकती है। यहीं नहीं लगातार जैविक खाद के प्रयोग से फायदा यह हुआ कि आस.पास के खेतों के मुकाबले इस जमीन में सूक्ष्म तत्वों में भी इजाफा हुआ है। यहां पर केवल जैविक खाद ही मिट्टी में नहीं डाली जा रही है बल्कि जैव विविधता पर ध्यान दिया जा रहा है। श्री माली ने कहा कि आगे वह अब पूरे खेत में जैविक खेती करेंगे। इसमें न केवल जैविक तरीके से खेत तैयार करें बल्कि फसलों में भी जैविक घोलों का उपयोग करेंगे, जिससे जहरीली फसल के बजाय सेहत के लिए फायदेमंद फसलों का उत्पादन हो।

मौसम में आया बदलाव, फसलों के लिए जारी कि एडवायजरी

समूचे प्रदेश में इस शीत ऋतू के दौरान थोड़े.थोड़े अंतराल में मौसम में बदलाव आता रहा है। मौसम को देखते हुए किसानों को फसलों के रखरखाव को लेकर भी सलाह जारी की गई है। जिले में रबी फसले की लगभग कुल 3 लाख 75 हजार 381 क्षेत्रफल हेक्टेयर में बोनी की गई है। मप्र के खरगोन में जिला स्तरीय डायग्नोस्टीक टीम ने गोगावां के ग्राम दशनावल के कृषक गोपाल राजू, सुरज देवीलाल, टव दुधा, ग्राम सोलना के कृषक तुकाराम थापा, ग्राम घुघरियाखेड़ी के बेलरसिंह रेसला के खेतों में फसलों का अवलोकन किया।

कृषि उप संचालक एमएल चौहान ने सलाह दी है कि चना फसल में कीटों का प्रकोप अधिक होता है। ऐसे में कीट नियंत्रण सर्वप्रथम मेकेनिकल विधियों से किया जाना चाहिये। इसमें टी आकार की खूटियां (35.40 प्रति हेक्ट) लगाये, जिससे कि पक्षी उन पर आकर बेठेंगे व इल्लियों को खाकर उन्हें नियंत्रित करेंगे। खूटियां फली में दाना भरते समय निकाल दे। जैविक विधियों में एनपीव्ही वायरस 250 एलई का 500 एमएल प्रति हेक्टेयर उपयोग करे। चना में इल्ली का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर (1.2 लार्वा प्रति मीटल पंक्ति) से अधिक होने पर इसके नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवा फ्लूबेन्डामाईड 39.35 प्रतिशत एससी की 100 मिली प्रति हेक्टेयर या इन्डोक्साकार्ब 15.8 प्रतिशत ईसी की 333 मिली प्रति हेक्टेयर या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 प्रतिशत प्लस लुफेनुरॉन 40 प्रतिशत का 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर का 400.500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चने में फूलवाली अवस्था में सिंचाई न करे। चने में विल्ट से बचाव हेतु कुछ समय तक सिंचाई करने से बचना चाहिए। साथ ही जड़ सड़न रोग से बचाव के लिए ट्रायकोडर्मा विरडी 250 ग्राम का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर पौधों में ड्रेचिंग करे अथवा रिडेमिल 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जडों के आसपास ड्रेसिंग करे।

इसी प्रकार गेहूं फसल में कुछ.कुछ किस्मों में ग्लूम ब्लॉच नामक रोग देखा गया है। जिसकी रोकथाम के लिए आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र खरगोन के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. व्हाय. के जैन ने बताया कि प्रतिकुल मौसम जैसे कम तापमान एवं नमी अधिक होने कि दशा में यह रोग का संक्रमण हवा के द्वारा फैलता है। उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए प्रोपीकोनाजोल दवा का 15 एमएल प्रति पम्प के अनुसार घोल बनाकर छिड़काव करना करने को कहा। उन्होंने बताया कि गेहूं में इल्ली का प्रकोप होने पर इमामेक्टिन बेंजोएट 5 प्रतिशत का 8.10 ग्राम प्रति पम्प के अनुसार घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। भ्रमण दल में कृषि वैज्ञानिक डॉ. मितोलिया, सहायक संचालक कृषि पियुष सोलंकी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी टीएस मण्डलोई, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गिरधारी भावर एवं ग्राकृविअधि. जितेन्द्र सोलंकी उपस्थित रहे।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन।.RNI No. MPHIN/2022/85285, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।